Seventeenth Loksabha

n lang=HI>

Title: Need to review the decision to phase out IASE, CTE and DIET from 1 April, 2020 - Laid.

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान स्कूली शिक्षा मैं गुणवत्ता सुधार की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा । वर्तमान सरकार हमेशा से ही स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर प्रयासरत रही है । इसी कड़ी में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजस्थान सहित सम्पूर्ण देश मैं सर्व शिक्षा अभियान योजना लागू की गयी थी । इसी योजना के तहत सम्पूर्ण देश में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ नवाचारों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का कौशल विकास करना था ताकि देश में साक्षरता दर बढ़ सके एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मानव संसादन विकास मंत्रालय ने देश भर में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं जिसमे एक प्रयास देश भर मैं राजकीय शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार परवर्तित योजना के तहत आई ए एस ई. सी टी ई. डाइट जैसे संस्थाओं का गठन कर शिक्षा में आमलचल परिवर्तन लाने का प्रयास किया है किन्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की गाइड लाइन में 14 वे वित आयोग की समाप्ति पर आई ए एस ई, सी टी ई डाइट जैसी संस्थाओं को 1 अप्रैल 2020 से फेज आउट किए जाने की योजना बना रहा है । इन परीक्षण संस्थाओं को फेज आउट किए जाने से आई ए एस ई, सी टी ई डाइट संस्थाओं को ही 31 मार्च 2020 के बाद समग्र शिक्षा अभियान से बाहर किया कर दिया जाएगा । अप्रैल 2020 में यदि उपरोक्त संस्थाओं को बाहर कर दिया जाएगा तो राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने एव शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं को फेस आउट किए जाने से इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य के उच्च शिक्षा संस्थाओं में

समायोजित करने से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उपरोक्त योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर भी विराम लग जाएगा । अध्यक्ष महोदय इस समय सम्पूर्ण देश में 152 सी टी ई और 28 आई ए एस ई संस्थान संचालित हैं । राजस्थान राज्य के 8 सी टी ई संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों को विगत कई माह से वेतन एव अन्य भत्तों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लगातार इन्हे फेस आउट किए जाने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए जाने से इन संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है । अध्यक्ष महोदय राजस्थान राज्य समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य मे क्रमोनत 8 सी टी ई संसथाओं के सी एस एस के स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों के वेतन में अपना निर्धारित राजयांश 2018-19 में 58 प्रतिशत एंव 2019-20 में 64 प्रतिशत व्यय नहीं कर रहा है जिससे इन संस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ।

अत: मेरा से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजकीय विधालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उपरोक्त संस्थाओं को फेज आउट किए जाने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फैसले पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।